RAJYA SABHA

Monday, the 20th July, 1998/29 Asadha, 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** *in the chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Inclusion of Certain Castes/Tribes in the list of SCs/STs

*461. DR. RANBIR SINGH:†
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many State Governments have recommended for inclusion of certain castes/tribes in the list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes;

(b) whether it is also a fact that some states have recommended for treating some castes/tribes, being synonyms of certain castes/tribes already recognised as Scheduled Castes/Tribes in their respective States;

(c) if so, the details in respect of parts (a) & (b) above; and

(d) what action Government have taken or propose to take for inclusion of the recommended castes/tribes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The State Governments and Union Territory Administrations have recommended inclusion of 76 and 273 communities as independent entries in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively and another 148 and 290 communities respectively have been recommended for their specification as synonyms of certain existing Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(d) The matter is under consideration.

डा॰ रणबीर सिंहः महोदय, शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स का क्लासीफिकेशन उनकी सामाजिक और आर्थिक असमानता के आधार पर और इस असमानता को दूर करने की नीयत से किया गया था। इसके लिए उन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था और छुआछूत के खिलाफ आवश्यक कानून बनाए गये थे। इस कानून को बने 45 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है। मेरे देखने में यह आया है कि कुछ शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के परिवारों में कई-कई आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ जैसे पदों पर लोग आसीन हैं। मुझे लगता है कि रिज़र्वेशन का फायदा कुछ ही परिवारों या कुछ ही जातियों तक सीमित रह गया है। ऐसी हालत में मेरा सवाल यह है कि क्या हुकूमत ऐसा कोई सर्वे कराना चाहती है जिससे यह पता चले कि रिजर्वेशन का असर कितना व्यापक है? अगर नहीं तो क्या ऐसा सर्वे कराने की सरकार की कोई इच्छा है जिसके आधार पर शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ की सूची रिवाइज़ की जा सके?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, as I understood, he wanted to know whether certain families have taken advantage of reservation to go ahead. Sir, it is not the job of the Government to find out what the discrepancy is or whether certain families have got IPS or IAS officers or not. Our job, as I said, is to provide minimum amount of education, as is provided, to give them special concessions in terms of education, to see that they, as many as possible, can come forward. There has been a substantial increase in the number of people being recruited to Government services. I have the list with me. The number has increased substantially. In fact, in the case of class D, the number has gone up to 21 per cent. In the case of class C, the number has gone up to 16 per cent. In the case of class B, the number has gone up to 12 per cent and in the case of class A, the number has gone up to 15.16 per cent. So the Government cannot possibly do a house to house survey on who has

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ranbir Singh.

taken advantage of that unfairly. Unfairness exists in every system.

डा० रणबीर सिंह: मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सो काल्ड अगड़ी जाति में पैदा तो हुए हैं लेकिन वे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब लोगों से भी नीचे के स्तर पर जी रहे हैं। किसका कहां जन्म हो, किस जाति में जन्म हो यह किसी पर डिपेंड नहीं करता है और न किसी का इसका कोई राइट बनता है। ऐसे लोग अक्सर भीख मांगने पर मजबूर रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या हुकूमत ऐसे लोगों को, जो सो काल्ड अगड़ी जाति में हैं और अत्यन्त गरीब हैं, इनको भी रिजर्वेशन का फायदा देने के बारे में सोचेगी? यानी आर्थिक स्टेटस भी रिजर्वेशन का आधार बन सकता है या नहीं और उनको भी रिजर्वेशन की सूची में जोड़ा जा सकता है या नहीं?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: This is an excellent suggestion. One thing which has been there in the minds of many people for some years now is that perhaps reservation should be done on economic basis rather than on caste basis. Unfortunately, the Government has no plans to do it.

श्री राम नाथ कोविन्द: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 948, जो 2 जून, 1998 को दिया गया था, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, वह प्रश्न यह था कि राज्य सरकारों ने जिन अनुसूचित जन-जातियों को इस सूची में शामिल करने को लिखा है, उसका ब्यौरा क्या है। उनका उत्तर था कि "अनुसूचित जन-जातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के लिए 691 प्रस्ताव प्राप्त हुए है।" सभापति महोदय, आज यह जो उत्तर दिया गया है उसमें जो तथ्य है यह उससे बिल्कुल भिन्न है, वह इससे मेल नहीं खाते। आज के तथ्यों में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 273 कम्युनिटीज की रिकमन्डेशन की गयी है। यह डिसक्रैपेंसी क्या है, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं?

दूसरा, जो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, वह यह है कि वर्तमान सूची में जो एस०सी० और एस०टी०जातियां हैं उनको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, यह हम सब जानते हैं और जो इसमें नहीं हैं वे अपने को इसमें जोड़ना चाहते हैं। महोदय, आरक्षण की नीति निष्ठा से आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एक ही जिम्मेदार है, इलिटिस्ट ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार है। महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लागू करने की जो विधि अपनाई गई है वह केवल आफिस मेमोरेंडम के थ्रू की जाती है। जो कोर्ट के आर्डर आते हैं, जो एस०सी० और एस०टी० के खिलाफ होते हैं उनके आफिस मेमोरेंडम तो रातों रात इश्यू होकर उनका इम्पलीमेंटेशन शुरू हो जाता है और जो उनके हक में होते हैं, वे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अभी पिछली बार जो सोशल जस्टिस की सरकार, 1997 में थी, उस समय पांच आफिस मेमोरेंडम इश्यू हुए थे और उनका तुरन्त इम्पलीमेंटेशन शुरू हो गया था। महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि 77 कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो इस सदन ने भी पास किया इसमें आर्टिकल 16(4ए) संविधान में जोड़ा गया और उसमें यह कहा गया कि "Reservations in promotions will apply to any class or classes of posts and services in favour of SC/ST." लेकिन कंसिक्वेंटली, जो उसका आफिस मेमोरेंडम इश्यू हुआ है उसमें उसकी स्प्रिट इससे बिल्कुल भिन्न है। महोदय, 1977-78 में बहुत सारी डिसक्रीपेंसीज़ हुई और इसको देखते हुए इसी साल एक समिति बनी, एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी माननीय सूरज भान, जो आजकल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी। यह जितनी डिसक्रिपेंसीज है, किन जातियों को एक्सक्लूड करना चाहिए, किनको इन्कलूड करना चाहिए, आफिस मेमोरेंडम ठीक स्प्रिट में क्यों इश्यू नहीं होते हैं, इसके लिए मेरा प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा विचार करेंगी कि जितनी शैड्यूल्ड कास्ट संबंधी डिसक्रिपेंसीज़ हैं, चाहे वह एस०सी०, और एस०टी० के बाबत हों, चाहे रिजर्वेशन के बाबत हो तथा चाहे वह आफिस मेमोरेंडम से संबंधित हो, क्या इसके लिए कोई ज्वाइंट पालिर्यामेंटरी कमेटी सेट-अप करेंगें? साथ ही क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, नेशनल कमीशन फार एस०सी०/एस०टी० जो है उसको रेफर करेंगे, क्या उनके साथ मिलकर कोई एक्स्टरा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Actually, it has been such a long question that several questions have been clubbed with it. The hon. Member started with the discrepancy in the figures given by the last Government and what have been recommended for reservation. It is quite true that the figures are different. The figures are different because they have increased substantially. The figures that I

have quoted, 76 and 373 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are those that have been officially given to us by States. In actual fact, we have 1,400 proposals which have been given by different groups. Out of these, we have some that have been given to us by States and rejected by the Registrar General of India because they don't tally with the figures; some have been given by different commissions and they don't tally with either the State wanting them or the Registrar wanting them. So, there are a plethora of people and commissions that have to be consulted before any action can be taken on anyone of them. The figures change virtually from week to week and new groups discover that they want to be in Scheduled Castes and Scheduled Tribes and petition their State Governments or lobby for them from time to time. So, those figures will change.

Secondly, I am not aware of any office memorandum which as specifically been applied or not applied. Perhaps, I can have a look because I don't think there is any office memorandum referred to my Ministry on which action is to be taken. Perhaps, this is an intra-office memorandum pertaining to some particular Ministry because we have not found such a thing.

Thirdly, he asked whether we should have a Joint Parliamentary Committee. No, I don't think so. We already have a very effective National Commission and everything is referred to it regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI SATYANARAYANA DRONAMRAJU: Mr. Chairman, Sir, you are well aware that the fishermen of Andhra Pradesh along the coastal area are living in abject poverty and are affected by natural calamities. They don't have any other source of livelihood. Sometimes they die in abject poverty. Consequently, their children are forced to sell fish in order to support their families. The fishermen community of Andhra Pradesh has already been recommended by various Central Commissions and State committees for including them in the list of Scheduled Tribes. I would, therefore, like to know from the hon. Minister whether the Government of India has received any proposal from the Government of Andhra Pradesh and whether the Government has accepted the recommendations of various committees for including this community in the list of Scheduled Tribes. If so, the details thereof.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: The Government has received a number of requests or recommendations from the Government of Andhra Pradesh and perhaps, fishermen are one of them. Unfortunately, no action can be taken at this point of time to any single person or any single group in the list of SC or ST as that would require coming back to Parliament. Since there are 1,400 requests, the best thing that is being thought of is that it goes to the National Commission; it gets concurrence from the Registrar General of India in consultation with the State Governments and when all the three agree—all the three have not agreed on any single one so far—we would be happy to place it before—the Cabinet Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and after it passes that, we would come before the Parliament.

SHRI SANATAN BISI: Mr. Chairman, Sir, as per the Government of India Brochure on SCs and STs in Service, VIIth edition, 1987, page 375, Dhibara, Keuta, Kaibarta have to be treated as synonymous names of Dewar community which already been specified as Scheduled Caste in relation to the Orissa State. What are the reasons for delay in including them in that list?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Whatever has been notified, is already there. So, there is no delay in it.

SHRI SANATAN BISI: What are the reasons for the dealy? It had been notified in the Brochure of the Govern-

ment of India as far back as 1987. Till today, it has not been included.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: I just have to keep repeating this *ad nauseam,* i.e. the procedure for putting them into this list is so complicated that either we simplify the procedure in which case we will have another flood of recommendations or we work out modalities. Till today, the modalities for making somebody SC or ST, putting a group in, have not been worked out. This Ministry has, for the first time, worked out modalities. We are going to the Cabinet. Once we work out the modalities, then everybody will know if they fit into one. If they fit the requirement, it will be notified.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: I want to know one thing from the hon. Minister. A report of the Select Committee on the continuation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 1986, in respect of Assam, was presented to the Lok Sabha on the 12th August, 1997. The Committee recommended certain tribes to be included in the Constitution as Scheduled Tribes. What are those tribes to be included into? Secondly, when would this Bill be brought to give them the status of Scheduled Tribes?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Whether it is Assam or Maharashtra or Andhra Pradesh or any other State, the same answer will apply to all. You may recommend or the State may recommend certain people to be included or a certain group to be included. It requires a Bill to come before the Parliament. I cannot bring a Bill every second week because of one particular community. It has to be done comprehensively. We have to take the Parliaent seriously.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: The Select Committee was there and it recommended it.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Yes, there are certain things that are recommended. We are just awaiting clearance for all the 1400, whether 'yes or 'no', so that we can bring it forward.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः आनरेबुल चेयरमैन साहब, त्वाडे जरिए मैं आनरेबुल मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके लिहाज से क्या मिनिस्टर साहब सोचेंगी कि देश के जो वीकर सेक्शन्स है उनको भी इस लिस्ट में और एड किया जाए और इस 25 परसेंट रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया जाए ताकि बाकी अदर क्लासेज के वीकर सेक्शन्स भी इसमें आ जाएं और फायदा उठा लें इस स्कीम से?

(SHRIMATI MANEKA GANDHI: Actually I have answered this question. As I have said, we would be happy to do it on economic basis. That is not the policy of this Government or any Government that has gone into.

MR. CHAIRMAN: It is already twenty minutes. Q. No. 462 now.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रगति दर

*462. श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः†
श्री बरजिन्दर सिंहः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1998 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "पैनल डिससैटिस्फाइड विद एस०सी०/एस०टी० प्रोग्रेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास की दर संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, और भविष्य में इस दर में सुधार हेतु योजना का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 24.4.1998 के नई दिल्ली के संस्करण "पैनल डिससैटिस्फाइड विद एस०सी०/एस०टी० प्रोग्रेस" शीर्षक से कोई लेख नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

†सभा में यह प्रश्न श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा पूछा गया।